(1)ओमप्रकाश मंजुल,पीलिभीत,उत्तर प्रदेश, ज्ञानतत्व–6011

प्रश्नः– एक समय था,जब अल्लामा इकबाल की लाइन,''मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना'' को मानवीय भाई चारा का मंत्र माना जाता था। इसका जादू कुछ वर्षो पूर्व तक बाकायदा बरकरार भी रहा था। पर,आज हम विश्व स्तर पर मुसलमानों में आपसी मारकाट की मची होड़ पर दृष्टि डालते हैं,तो लगता है इस पंक्ति में निहित जादुई शक्ति की हवा निकल चुकी है। जिस इस्लाम के भाई चारा की तारीफ में लोग कसीदे पढ़ते हुए नहीं अघाते थे,आज वह भाई चारा बुरी तरह आहत और क्षतिग्रस्त हो चुका है। आज ''मुस्लिम भाईचारे'' का मतलब 'भाई ही भाई का चारा' हो चुका है। हालॉकि इकबाल के'आपस' से आशय मात्र मुस्लिम–मुस्लिम के बीच नहीं था। कुरान शरीफ में भी जिस भाई चारे की बात कही गई है वह भी केवल मुसलमानों के बीच का भाई चारा नहीं है। इनके भाई चारे का तात्पर्य है' इंसान–इंसान के बीच मोहब्बत और मित्रता। यह चाहे मुस्लिम के बीच हो या मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच हो। इनके भाई चारे का अर्थ अखिल वैश्विक सद्भाव से है। चाहे लोग किसी भी जाति,देश,मजहब,धर्म या पूजा पद्धति के हों। आज हम मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा दुनिया में की जा रही हिंसा पर दृष्टिपात करते है, तो लगता है मुस्लिम ब्रदरहुड आकाश कुसुम हो चुका है।

आतंकवाद आज ही नहीं उपजा है। यह पचासों साल पूर्व भी था। पर उस समय यह उग्रवाद तक सीमित था। आज जैसा खुंखार और जल्लाद नहीं। न ही यह आज की भांति मजहब को लेकर अन्धा व पागल बना था। आयरलैण्ड, भारत, श्रीलंका, लंबे समय तक आतंकवाद से त्रस्त रहे है। पर इन देशों में आतंकवाद क्षेत्र को लेकर रहा है,धर्म और मजहब को लेकर नही। आयरलैंण्ड का उग्रवाद ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने के लिए था,पंजाब में खलिस्तान,असम में बोर्डोलैण्ड और श्रीलंका में तमिल क्षेत्र को लेकर था। कश्मीर के आतंकवाद में क्षेत्रवाद और मजहबवाद दोनों का मिला जुला रुप रहा है। पर इन आतंकवादी अभियानों में ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवादियों ने कश्मीर और अफगानिस्तान को छोड़कर अपने ही मजहब और धर्म वालों की निर्ममता पूर्वक हत्या की हो।

जब हम मुस्लिम आतंकवाद पर दृष्टि डालते है,तो ऐसी–ऐसी विकराल वीभत्स और विरोधाभासी चीजें सामने आती है,जिनका सही चित्रण कर पाना बहुत कठिन है। आतंकवादियों के पैशाचिक कृत्यों के नित नये समाचार न केवल खून से सने हुए,अपितु इंसानियत को शर्मसार करने वाले आ रहे हैं। यू तो से खबरें रोज ही प्रत्येक भाषा के दैनिकों में आ रही है,पर इन समाचारों का जितना त्वरित,तटस्थ और संतोषजनक प्रसारण बी.बी.सी. की भाषायी सेवाओं द्वारा किया जाता है,उतना किसी भी समाचार देने वाली एजेंसी द्वारा नही किया जाता। बी.बी.सी. के दैनिक समाचारों में कुछ हो या न हो पर रोज ही दुनिया के किसी न किसी भाग में चरमपंथियों द्वारा किये जाने वाले कत्लेआम की खबर होती है। बी.बी.सी. की खबरें सुनकर लगता है कि दुनिया में हर जगह चरमपंथियों द्वारा की जाने वाली हिंसा की आग लगी हुई है और मजहबी पागलपन से ग्रस्त लोग ऐसे अंधकार में मारकाट कर रहें हैं, जिसमें यह भी पता नहीं चलता कि मारे काटे जाने वाले दीगर है या अपने । समाचारों के दर्पण में यदि आतंकवादियों की निन्दनीय करतूतों को देखें,तो ''इस्लामिक स्टेट' आई एस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन जो अलकायदा और लश्करेतैयबा के ही बदले हुए रुप है न केवल बूढ़ो,बच्चों,जवानों और औरतों को ही मार रहे हैं,अपितु औरतों के साथ वह खौफनाक,दर्दनाक और शर्मनाक सलूक कर रहे हैं,जिसे सुनकर आदमी के रोंगटे खडे हो जाते हैं और खून खौलने लगता है। बोकोहराम ने अप्रैल 2014 में नाइजीरिया से लगभग 300 किशोरियॉ अगवा की थी,जिसमें से 50–60 युवतियॉ किसी तरह से उनके चंगुल से मुक्त होकर आ गयी। इनमें लडकियों के साथ बोकोहरामियों के बर्ताव की बड़ी रोमांचक और लौमहर्षक कहानियॉ सुनाई है। हरामी इन लडकियों के साथ मनचाहा व्यवहार कर रहें है। उन्होने इन्हें आपस में बॉट लिया है। इस समय वे इन्हें अपनी बीबी बनाकर इनके याथ यौनाचार भी कर रहे है तथा अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण देकर घाती और आत्मघाती हमलों में भी उपयोग कर रहे है। आई एस वाले पकड़ी गयी महिलाओं के साथ हवश तो पूरी करते ही है, जरुरत पड़ने पर उन्हें सिग्रेट से भी सस्ती कीमत पर बेच देते हैं। इनके पास ऐसी हजारों महिलायें है और सीरिया आदि के शहरों के बाजारों में उनकी बाकायदा नीलामी हो रही है। चरमपंथी इन्हें नंगा नहलाने के बाद ग्राहक के सामने पेश कर देते हैं। यू.एन.ओ.की दूत,सुश्री जैनब बागुरा ने ठीक ही कहा है, यह ऐसी लडाई है जो महिलाओं के जिस्मों पर लड़ी जा रही है। धरोहर योग्य कलात्मक मूर्तियों को ये लोग तालिवान द्वारा बामयान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिये जाने जैसी तर्ज पर खंड खंड कर देते है।

कभी आयरलैंण्ड,अफगानिस्तान और भारत में ही आतंकवाद होने की बातें की जाती थी। आतंक और नरसंहार का सर्वाधिक दंश भारत के कश्मीर ने झेला है,जहॉ गत 62 वर्षों से मुस्लिम चरमपंथियों ने अपने ही मजहब के पचासों हजार मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। आज स्थिति यह है कि पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नही बची, जहॉ आतंकवाद आबाद न हो। अपवाद को छोड़ दें, तो आतंकवाद मुस्लिमों के द्वारा प्रयोजित ही नही सुनियोजित भी रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमरीका 11.09.2001 ग्रेट ब्रिटेन ब्लास्ट 7.7.2005 बॉम्बे ब्लास्ट भारत 26.11. 2008 शार्ली शब्दो से सम्बद्ध फ्रांस की राजधानी पेरिस 07.7.2015 तथा इससे कुछ वर्षो पूर्व फ्रांस हमले के ही मूल,मोहम्मद साहब के काटूॅन से कनैक्टेड डेनमार्क में हुए बवाल जैसे कांड इसके ज्वलंत प्रमाण है। आज आतंकवाद कहॉ नही है?

सुनते है मुसलमानों के पाक ग्रन्थ में 73 प्रकार के मुसलमानों का जिक्र है। एक प्रकार का जन्नती और 72 प्रकार के जहन्नुमी फिरके है। विडम्वना यह है कि इनमें हर फिरका अपने को जन्नती बताता है अलकायदा लश्करे तायबा आईएस अलशबाब, बोकोहराम, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, जुनदुल्लाह, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान लश्कर ए झंगबी अलनुसरा हमास हक्कानी नेटवर्क आदि अनेक संगठनों के पीछें सुन्नी फिरकाओं की भूमिका रही है। शियाओं में नाममात्रेण फिरके ही हैं,वे भी चरमपंथी न होकर विद्रोही प्रवृत्ति के है जैसे यमन में होती गुट। पर जहॉ तक सुन्नियों का सवाल है, तो मुस्लिम देशों को छोड़ भी दें तो अकेले हिन्दुस्तान में ही इनकी बरेलवी बहावी देवबंदी,रजबी,सकलैनी आदि अनेक शाखाएॅ है। हालाकि शिया सुन्नी दोनों ही अपने को असली और दूसरे को नकली मुसलमान मानते हैं। शिया कहते है कि सुन्नी जाहिल है और सुन सुन कर मुसलमान बने है और सुन्नी कहते है कि शिया पतित है और रसूल साहब पर ईंसान नहीं लाते। फिलहाल पूरी दुनिया में चरमपंथ ने मजहब के नाम पर आपस में ही विकट मार काट मचा रखी है। ऐसी स्थिति में इस्लाम दुनिया के दूसरे दीन धर्मों को भाईचारे की सोच क्या दे सकेगा?

लेख में वर्णित आतंकवाद का आधा अधूरा वर्णन विशेष रुप से इन 2–3 महीनों सहित सामान्यतः एक वर्ष का है। इस समय अकेले सीरिया के 40 लाख लोग शरणार्थी शिविरों में पडे हुये है, जिसे यु.एन.ओ. के सेक्रेटरी,एंटोनियों ने सदी की सबसे बडी त्रासदी बताया है। यदि आतंकवाद का कहर ऐसे ही जारी रहा और आतंकवादी नरसंहार के लिए भविष्य में नई–नई तकनीकों,तरीकों और तरकीबों को अपनावते रहे,तो भविष्य की कल्पना भी भयावह है।

उत्तरः— आपने इस्लामिक कट्टरवाद का जो भयावह चित्र खींचा है स्थिति उससे भी अधिक भयावह है। प्रश्न यह है कि इस वैश्विक परिस्थिति में भारत और भारत के हिन्दुओं की भूमिका क्या हो यह विचारने की जरुरत है। दुनिया चाह सकती है कि आगामी विश्व युद्ध भारत में ही हो।

संभव है कि कट्टरवादी मुसलमान भी ऐसा ही चाहेंगे। संभव है कि भारत के संघ परिवार के लोग भी नासमझी में ऐसे प्रयत्नों को हवा दें किन्तु ऐसा होना भारत के खासकर हिन्दुओं के लिए बहुत दुखद होगा। मुसलमान जहॉ भी होता है वहॉ आंशिक रुप से अथवा पूरी तरह स्वयं को शेर के समान ही समझता है,दूसरी ओर हिन्दू आमतौर पर अपने को गाय के समान रहने में ही संतुष्ट और प्रसंन्न रहता है। संघ के लोगो को 80 वर्ष इस प्रयत्न में लग गये कि हिन्दुओं को गाय से हटाकर शेर बना दिया जाये लेकिन परिणाम स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में भी हिन्दू 67वर्षो तक दोयम दर्जे का बनकर जीवन जीता है। अब भी नरेन्द्र मोदी के आने के बाद भी ऐसा कोई लक्षण नही है कि हिन्दुओं को शेर बना दिया जाये,स्वयं नरेन्द्र मोदी भी इस लाईन को ठीक नही समझ रहे।क्या यह उचित नही होगा कि हिन्दुओं को शेर बनाने की दिशा में बढ़ाने के प्रयत्नों को छोड़कर तथा अनुचित मानकर मुसलमानों को गाय के सरीखे बनने की दिशा में बढाया जाये या मजबूर कर दिया जाये? क्या यह उचित नही होगा कि स्वतंत्र भारत में राजकीय हिंसा के अतिरिक्त किसी प्रकार के हिंसा या बलप्रयोग को अनुचित,अनावश्यक मान लिया जाये। मैं आपकी इस बात से सहमत हूॅ कि मुसलमानों को शांतिप्रियता की ओर जाने के लिए सहमत करना बहुत कठिन है किन्तु हिन्दुओं को प्रत्यक्ष टकराव की दिशा में प्रेरित करना और भी अधिक कठिन है। राज्य भी गाय को शेर बनाने में मद्द नहीं कर सकता किन्तु शेर को गाय बनने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि भारत में अन्य सब को छोडकर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाये तो बहुत कुछ सुधर सकता है। यह कदम संभव भी है यदि हमारे ना समझ मोहन भागवत हिन्दू राष्ट्र की अपनी जिद छोड़ दें। भारत को किसी भी परिस्थिति में विश्व

युद्ध की तरफ ढकेलना बहुत घातक होगा। आवश्यक है कि भारत में थोडा झुककर भी साम्प्रदायिक, सौर्हाद्र बना रहें तो अच्छा है। कश्मीर युद्ध क्षेत्र बन सकता है। इसलिए कश्मीर के बारे में वर्तमान सरकार बनाने का प्रयोग भी बहुत उचित और साहसपूर्ण कदम है। आपने जो कुछ लिखा वह भारत के मुसलमानों के लिए अधिक विचारणीय है और भारत के हिन्दुओं को इस मामले में कुछ तठस्थ रहना चाहिए। मैं फिर से आप से निवेदन करुँगा कि आप इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दो को सोचसमझकर आगे बढ़ावे। मैं आश्वस्त हूँ कि दुनिया इस्लामिक कट्टरवाद को अच्छी तरह समझ रही है। दुनिया के अनेक मुस्लिम राष्ट्र भी ऐसे कट्टरवाद के विरुद्ध खड़े होने की तैयारी कर रहें है। भारत को चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में आंतरिक साम्प्रदायिक टकराव न होने दे।

(2)रामकृष्ण,अभिनेक्ष, कानपुर उ0प्र0, ज्ञानतत्व 3972

प्रश्नः— आपका प्रयास उपयोगी सराहनीय तथा अनुकरणीय है। मैने अपने एक पत्र के माध्यम से कुछ ऐसा ही संकेत दिया था जिसकी आपने प्रशंसा की ही थी। मेरे आपके चिंतन का लक्ष्य एक ही है। आप भी देशहित चाहते हैं और मैं भी। आवश्यकता मतैक्यता की है। मतैक्यता गोष्ठी,विचारों के आदान प्रदान से ही संभव है। इसी संदर्भ में भविष्य में एक सहायक प्रयास का सूत्रपात मैने कर दिया है। यह प्रयास राष्ट्र भाषा हिन्दी को उसका स्थान और सम्मान दिलाने का है जिसके प्रचार और प्रसार के लिए मेरे दो पत्र निवेदन और अनुरोध इसी पत्र के साथ संलग्न है।

सच तो यह है कि वांछित लक्ष्य पाने के लिए ऐसे कई प्रयासों का श्री गणेश होना है जिनको साकार करने की योजना बनाने में मैं व्यस्त हूँ। फिर भी मैं आपको पूरा सहयोग दूँगा। यह मेरा संकल्प है। स्मरण रहे सहयोग,शारीरिक और बौद्धिक ही दे सकता हूँ। आर्थिक सहयोग देने की स्थिति में मैं नही हूँ।

समिति में सदस्यता का निर्णय आपके विवेक पर निर्भर है। इतना अनुरोध अवश्य है कि पद लोलुप व्यक्तियों से सावधान ही रहें। दृढ़ संकल्प योग्य कर्तव्य परायण साहसी पराक्रमी निर्भीक जागरुक और विवेकी व्यक्तियों को प्राथमिकता दें क्योंकि ऐसे गुण सम्पन्न लोगों को संगठित कर एक मंच पर लाने की अति आवश्यकता है।

उत्तरः— यह सही है कि आपके प्रयत्न और मेरे प्रयत्न लगभग एक ही दिशा में है। यह बात अलग है कि आप उन्हें देशहित कहते है और मैं समाजहित। आप हिन्दी के लिए जो कार्य कर रहें है वह बहुत अच्छा है। बहुत वर्षो तक हिन्दी के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। अब आप सबके प्रयत्न से हिन्दी को समान अवसर मिल जाये यह देशहित से अधिक समाजहित का काम है। मेरा आपके कार्य में पूरा सहयोग रहेगा। आपने पद लोलुप व्यक्तियों से दूर रहने का सुझाव दिया किन्तु पदलोलुपता नियंत्रण वहॉ सतर्कता खोजती है जहॉ अधिकार और कुछ आर्थिक अथवा शक्तिदायक लाभ की गुंजाइश हो । हमारे आपके इस प्रयत्न में कोई न शक्ति मिलने के अवसर है न ही कोई आर्थिक लाभ के। अतः संदेह की कोई गुंजाइश नही है फिर भी आप जैसे मित्र साथ है तो किसी प्रकार की गलती का गुंजाइश नहीं रहेगी।

(3)जगशरण उपाध्याय,दौराला,मेरठ ज्ञानतत्व, 9428

प्रश्नः— अंक 316 के संदर्भ में मेरा मत है मंदिर आस्था का पवित्र स्थान है, जिसमें राम और रावण दोनो अपने ईष्ट की उपासना कर सकते हैं। इसी प्रकार मस्जिद और गिरिजा घर आदि ईष्ट देवों की प्रार्थना के स्थल हैं, जहॉ व्यक्ति के मनोभाव में परम सत्ता के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। यदि रसखान को मंदिर में और नानक को काबे में जाने से रोका जाय तो धार्मिक सकीर्णता है। ज्ञान रुपी प्रकाश की खोज में मानव को कहॉ ज्ञान मिल जाये,उस स्थल को किसी परिधि में नही रखा जाना चाहिये। स्वार्थपरक धर्म व्यवसाई मानव मानव के मध्य दूरिया घटा नही पा रहे हैं। फिर वसुधैव कुटुम्बकम् के देश से विषमता कैसे दूर हो।

उत्तरः— मैं आपसे सहमत हूँ कि सभी धर्म स्थलों में दूसरे धर्म के लोगों को बेरोकटोक जाने की अनुमति होनी चाहिए। किन्तु यदि कोई वहॉ नियम विरुद्ध कार्य करें तो उसे रोका जा सकता है। व्यक्ति को रोका जा सकता है। किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं। ऐसा करना प्रत्येक धर्म वालों का कर्तव्य है। किन्तु दूसरे धर्म वालों का

अधिकार नहीं है। सब हिन्दू अपने को शांतिप्रिय सहिष्णु कहते हैं और दूसरे धर्म वालों से अपनी अच्छी पहचान बनाकर रखना चाहते हैं तो दूसरे धर्म की बुराईयों को देख देखकर उनके अनुसार अपनी नीति बनाना उचित नहीं। आपने लिखा कि देश की विषमता कैसे दूर हो,मेरे विचार में देश की विषमता दूर करना हमारा काम नही है। देश की राजनैतिक विषमता देश की सरकार को दूर करनी चाहिए। आर्थिक विषमता सरकार और समाज को दूर करनी चाहिए। तथा सामाजिक विषमता दूर करना सिर्फ समाज का काम है,हमारा काम है। इससे सरकार को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सच्चाई यह है कि राजनैतिक विषमता सरकार बढ़ा रही है और आर्थिक विषमता बढ़ाने में सरकार और समाज दोनों सक्रिय हैं तथा सामाजिक विषमता बढ़ने का कारण सिर्फ सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है। सरकार अपना काम अर्थात् राजनैतिक विषमता दूर करने का काम न करके सामाजिक विषमता दूर करने के नाम पर अनावश्यक हस्तक्षेप करती है जिसका परिणाम होता है सब प्रकार की विषमता में वृद्धि।

(4)सत्यपाल शर्मा,बरेली,उ0प्र0 ज्ञानतत्व–6894

प्रश्नः— प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2.7.2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लांच करके भारत को आधुनिक देश बनाने की बात कही है। कार्यक्रम शुरु करने से पहले मोदी जी देशवासियों को बताते कि डिजिटल इंडिया क्या है, इससे आधुनिक भारत कैसे बनेगा तथा आधुनिक भारत का स्वरुप क्या होगा? चरित्रवान नागरिक ही देश की असली पूँजी है। सरकार का पहला नैतिक दायित्व नागरिको के जान माल की सुरक्षा प्रदान करना तथा न्याय दिलाना होता है। केन्द्र व राज्य सरकारें दोनो इस राजधर्म का पालन करने में असफल हैं। जब तक देश के कर्मचारी पूरी तरह से ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्र भक्त नही होंगे तब तक आम नागरिक सुखी नही हो सकता। विदेशों की नकल करके वाहवाही लूटने के लिए किसी योजना को जल्दबाजी में लागू करना जनहित में नही हैं। मोदी जी सरकारी कामों को कंप्यूटर इंटरनेट में जोडकर आधुनिक भारत का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरु करने से पूर्व उसके उपयोग की पूरी जानकारी नागरिको को कराना जरुरी हैं। ए.टी.एम.खातो से आम नागरिको के आये दिन रुपये निकल जाते हैं इसकी छतिपूर्ति बैंक करें। देश के नागरिको के हित में नई योजनायें लागू की जायें।

उत्तरः— मेरे विचार में नरेन्द्र मोदी का हर कदम विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहा है। जिसका अर्थ है दूनिया के अन्य विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करना। मैं आपसे सहमत हूँ कि सरकार को सुरक्षा और न्याय पहले करना चाहिए। पिछली सभी सरकारों ने सुरक्षा और न्याय की भी अन्देखी की,और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी कुछ नहीं किया। नरेन्द्र मोदी यदि सुरक्षा और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते तो अधिक अच्छा होता। किन्तु यदि उन्होने सुरक्षा और न्याय की अन्देखी कर दी और विकसित भारत बनाने को अपना पहला लक्ष्य बनाया तो यह कार्य पिछली सभी सरकारों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। हमें नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा करनी चाहिए। भले ही हम साथ में सुरक्षा और न्याय की भी सलाह देते रहें। मेरा अपना आकलन है कि नरेन्द्र मोदी के आने के बाद उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार घटा है डिजीटल इंडिया की दिशा में जिस तेजी से सरकार बढ़ रही है उससे भ्रष्टाचार और अधिक घटेगा। लोगों को डिजिटल इंडिया की ट्रेनिंग देने का काम नीचे की इकाईयों का है। मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया की तेज गति के कारण अपने आप ट्रेनिंग की गति भी तेज हो रही है। यदि कोई विदेशी कार्य अच्छा हो रहा है तो उसकी नकल करना भी कोई बुराई नही है आलोचना कार्य की होनी चाहिए विदेशी या स्वदेशी का बहुत मामूली महत्व है। उसे बहुत ज्यादा महत्व देना अच्छी बात नही।

(5)शिवदत्त बाघा,बांदा,उ0प्र0, ज्ञानतत्व–7880

प्रश्नः— अपने विचारों को धरातल देने के लिए आपने व्यवस्थापक का जो संगठनात्मक रुप पेश किया है इसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकारें। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या? यह दुनिया धरती कुछ मुट्ठी भर धनवानों,रसूखदारों व राजनीतिवाजों, बडे बडे अलहकारों ओहदेदारों, के लिए ही बनी है। इसमें दुनिया की सात अरब आबादी का कही कोई वजूद नहीं है और है भी तो सिर्फ इन मुट्ठी भर लोगों की सुख सुविधा के जुँए के नीचे जुते रहने के लिए।साम्राज्यवाद व राजशाही की तर्ज पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नौकरों पर निर्भर होकर नहीं चलती। यह संवैधानिक रुप से गठित व संचालित लोकतांत्रिक इकाईयों के बूते चलती है जिसमें उसके मूल्य उसूल आदर्श और उद्देश्य

संरक्षित सवंर्धित शक्तिवान होते है। आपने जो देश का खाका खींचा है उसमें व्यवस्थापक अपने बनाने वाले के हर दरवाजे पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगा और उसके सुख दुख में शामिल हो सकेगा बजाय इसके कि अपने अवाम को वह व्यवस्थापक नौकरों के ऑख कान से देखे व सुने। यह अलग बात है कि मेरी उमर के लोग आपके लगाए इस पेड़ के मीठे फल न खा पाएँ किन्तु मौजूदा व आने वाली पीढ़ी इस पेड के मीठे फल चखेगी इस सुखद अनुभूति से ही मन गदगद हो जाता है। देश का यह संगठनात्मक ढ़ांचा व्यवस्था परिर्वतन के लिहाज से मील का पत्थर सावित होगा। आजादी के समय यह देश 565 देसी रियासतों में बंटा था। आज यह देश जातियों व फिरकों में बंटने की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए जातीय जन गणना पर दबाव बनाकर अपनी अपनी जातीय पट्टी इलाके बनाने की सोची जा रही है।

जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंदकर देश को जातीय आधार पर बांटने अथवा भूभाग पर कब्जे के मंसुबे बांधे जा रहे हैं। किन्तु आपके प्रयत्नों से इस तरह के षड़यत्रों पर विराम लग जाएगा और भारत की एकता अखडण्ता व आजादी भी सुरक्षित होगी।

मेरी उम्र 68 वर्ष है और चलने फिरने में भी असमर्थता है किन्तु फिर भी जो दायित्व मुझे दिया जाएगा विनम्रता के साथ उसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूँगा।हॉ लोक जिला के कार्य निर्वहन के लिए एक नाम आपके पास भेज रहा हूँ श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ चन्दन सिंह निवासी बाघा बांदा । मैं उम्मीद करता हूँ कि यह व्यक्ति 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक प्रस्तावित दिल्ली बैठक में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करायेंगे। मैं आपकी इस घोषणा से बेहद बदगद हूँ।

आध्यात्मिक क्षेत्र में अवतार, पैगम्बरों, वुद्ध पुरुषों,संत महात्माओं की एक अच्छी संख्या है। इन में कुछ महापुरुषों ने राजनैतिक क्षेत्र को भी साधने का प्रयास किया है,किन्तु सत्ता निर्माण की सामग्री यानी तत्व एक ही होने से इन महापुरुषों के जीवन काल के बाद शासकीय विकृतियॉ या शासन की परम्पराएँ पुनः पुनः अपना स्थान लेती रहीं। इसलिए हजार दो हजार क्रांतियों बदलावों की चाहत के बावजूद कोई सार्थक परिणाम जनता के हित में निकल कर सामने नही आए। राम राज्य की रट लगाने के लगातार प्रयास के बावजूद राम राज्य तो दूर उसकी परछाई तक देखना अब तक नसीब नहीं हुआ और न कोई ऐसी उम्मीद रखी जानी चाहिए जब तक बल आधारित सत्ता निमार्ण का कोई अन्य विकल्प सामने नहीं आ जाता। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी के वजूद के जो कारक है अस्तित्व उसके गुणों से निश्चित रुप से प्रभावित रहेगा। इसे ही पैतृक गुण या अनुवांशिक गुण कहते है। किसी बल के साथ यदि विवेक और नीति का सहचर्य है तो वह कल्याणकारी हो सकता है। और यदि बल इन से रिक्त है तो वह रावण की तरह अहंकारी होकर धरती को त्राहि त्राहि में डुबो सकता है। अपना देश ही नही समूची धरती आज त्राहि त्राहि में डुबी हुयी है। यह बात मैं नही कह रहा वरन् समूची दुनिया का मीडिया यह बात चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है और ऐसे ही दृश्य पेश कर रहा है। सारी दुनिया के लोगों की इस अमानवीय स्थिति से या व्यवस्था के नाम पर इस अव्यवस्था से उबरने,उबारने की अकुलाहट है। ऐसे विकट समय में आपका विचार आया शासक नहीं प्रबंधक जो इस पीड़ा को खत्म करने के लिए कारगर सिद्ध होगा। कोई भी शासक शासक के विचार से खुद में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह अपने कर्तव्य कर्म तथा आम जन की पीडा को भूल ही जाता है और निज वैभव विलासिता में डूब जाता है। वही जब किसी को यह एहसास कराया जाएगा कि वह शासक नहीं अपितु प्रबंधक है तो निश्चित रुप से वह लोगों की समाज की बेहतर सेवा के लिए यानी सुशासन के लिए खुद को अवश्य समर्पित करेगा।

आपने यह जो सुझाव पेश किया है, वह शासन जनित पीडाओं से मुक्त होने का एक मात्र विकल्प है। जिसे जोर दार तरीके से गति देना व चर्चावों में लाना अत्यन्त जरुरी है। अन्य विषयों से ध्यान हटाकर सारी वैचारिक उर्जा इसी दिशा में लगाने की जरुरत है। कहते है कि एकहि साधे सब सधे,सब साधे सब जाय। अगर प्रबंधक की अवधारणा ने चर्चावों में जोर पकड़ा, जमीन में गति पकडी तो धरती के पीडित जन निश्चित रुप से उसके पीछे खडे दिखेंगे क्योंकि व्यवस्था की बद इन्तजामी से हर सख्स परेशान है और जल्द से जल्द इस से निजात चाहता है।

आपने कहा है कि समाज राज्य सत्ता का गुलाम है। ऐसी तो अंग्रेजी साम्राज्य के दौर में भी समाज की स्थिति थी और आज भी है। तब फिर इस आजादी का क्या? जिसकी वर्षगाठ यह देश प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाता

है। तथा इस सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन का क्या? अर्थ जिसे लोकतंत्र कहा जाता है। आपके कहने का आशय यही हुआ कि गुलामी इस देश की नियति है। इस देश के सन्दर्भ में वास्तविक रुप से यही सच भी है।

15 अगस्त 47 को इस देश के राजनीति वर्ग को अंग्रेजो से कबडडी खेलने की स्वतंत्र रुप से इजाजत मिली। सम्भवतः यही आजादी है। 68 वर्षो से इस देश का राजनीतिक वर्ग सिर्फ कबडडी में नीचा दिखाने,जन बल,बाहुबल,धनबल प्रदर्शन का खेल खेल रहा है और अपनी धूर्ततापूर्ण इस कामयाबी के ढोल पीट रहा है तथा देश का वक्त जाया कर रहा है। जिसका भला होना चाहिए उसका कुछ भी नहीं हो रहा । यदि ऐसा कुछ भी हुआ होता या होता हुआ दिखता तो आप कदापि ऐसा नही कहते कि समाज राज्य का गुलाम है।

दरअसल लोकतंत्र का उस किताबी व रटाए गये अर्थ से अलग और कुछ भी अर्थ नही है। इस व्यवस्था का जमीनी अर्थ है शासन व समाज के बीच की दीवाल का खातमा उस दूरी को पाटना जो शासन और समाज के बीच में सदियों सदियों से चली आ रही है। लोकतंत्र हुकुमत का अर्थ है एक ऐसी सत्ता जो अपने को वजूद प्रदान करने वालों का योग श्रम संभाल रही हो, सुख दुख में भागीदारी निवाह रही हो समाज और शासन के रिश्तों के बीच किसी मध्यस्थ की जरुरत नही । आखिर लोकतंत्र में शासन का वजूद किस पर खडा है उसका जन्म दाता कौन?है। फिर लाल वत्ती में सवार होकर उस आम आदमी से दूर हटना दूर भागना खुद को वी आई पी घोषित करना लोकतंत्र का कौन सा रुप है। 68 वर्षो से कबडडी खेलने वाला देश का राजनीति वर्ग लोकतंत्र के नाम पर देश के साथ मतदाताओं के साथ यह छल कर रहा है और अपनी नामुराद उपलब्धियॉ गिना रहा है।

आपने संगठनात्मक रुप से देश को नया रुप देने की जो पेशकश की है तथा तद्नुरुप सरकार नही व्यवस्थापक का जो विचार सामने आया है निश्चय शासन समाज के बीच खडी दीवाल ढहाने में मद्द मिलेगी,दूरियॉ खत्म होगी तथा व्यवस्थापक हर उस दरवाजे में अपनी उपस्थिति दर्जकरा सकेगा जहॉ कोई मुसीबत खडी है।

नेकी कर कुऍ में डाल मतदाता 68 वर्षो से यही कर रहा है। बदले में उसे मुफ्त खोरी,रिश्वत खोरी,कालाबाजारी ,माफियागिरी,गुन्डागर्दी,हिंसा,अपराध,लूट पाट,घोटालों का बाजार मिल रहा है तथा खुद को अभावों घुटन की सौगात मिल रही है। इस स्थिति का खात्मा होना ही चाहिए और इसका एक मात्र रास्ता वही है जो आपने सुझाया बशर्ते इसमें भी कोई किसी प्रकार का भटकाव पैदा न हो।

आपने आडवाणी जी और मोदी जी को सोमनाथ मंदिर में गैर हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित करने के विरुद्ध सलाह दी है। अच्छा हो कि आप एक बार पदयात्रा की घोषणा करें। जो आपको रोक दिया जायेगा। किसी तरह आपको वेटिकन सिटी भी नही जाने दिया जायेगा। आपके सोमनाथ मंदिर संबंधी वक्तव्य पर फिर से विचार करने की जरुरत है।

उत्तरः— आपने व्यवस्थापक की योजना को ठीक से समझा। इससे हम सब सक्रिय लोगों को बहुत संतोष हुआ। आप इसी प्रकार हमें सलाह देते रहे। सोमनाथ मंदिर संबंधी मेरा सुझाव इस कारण है कि मैं कट्टर हिन्दू हूँ यदि मैं किसी अन्य धर्मावलंबी के घर में पैदा हुआ होता तो संभव है कि इसके विपरीत बोलता या यदि बोलता तो अकेला पड़ जाता। मुझे नहीं लगता कि सोमनाथ मंदिर अथवा अन्य मंदिरों में दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश रोक देने से हिन्दू धर्म का कोई भला हो जायेगा,बल्कि ऐसा कहते कहते हिन्दू धर्म और अन्य धर्मो का अन्तर घटता जायेगा। आज हम चुनौती भरे शब्दों में कहते है कि हिन्दुत्व धर्म है तथा अन्य सभी तथाकथित धर्म,धर्म न होकर संगठन मात्र हैं जिन्हें दूसरे शब्दो में सम्प्रदाय कहते है। यदि हमें कोई लाभ भी न हो और हमारी पहचान भी गिरने लगे तो अन्य सम्प्रदायों की देखादेखी आत्म संतोष के लिए अपना स्तर नीचे गिराना कोई बुद्धिमानी नहीं है।स्वतंत्रता के बाद हमारी संसद ने, राजनेताओं ने, जैसा आचरण बनाया, उसमें हमारे राजनेताओं का व्यक्तिगत दोष न होकर नीतिगत दोष है आप विचार करिये कि मैं एक छोटे से शहर रामानुजगंज का 2000 में नगरपालिका अध्यक्ष बना। मैं सोचता था कि भ्रष्टाचार नही होने दूँगा किन्तु एक महिने में ही मुझे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। मैंने पूरे शहर की आम सभा बुलाई और अपनी समस्या को रखा कि हमारे सरकारी कर्मचारी अपना ट्रांसफर कराना चाहते है तथा उपर से पैसा मंजूर कराने में भी घूस देनी पड़ती है अंत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ दस प्रतिशत तक घूस लिया जायेगा। सन् 77 में जब मैं राजनैतिक दृष्टि से जिला अध्यक्ष बना।मैं भी शक्तिशाली था तब हमारे मंत्रिमंडल के दोनों सदस्य तथा आठों विधायक गरीब होते हुए भी पूरी तरह इमानदार थे। आज उन्हीं इमानदार राजनेताओं के

बच्चे विधायक सांसद बनकर पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जबकि हम लोगों ने इन बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग भी दी है। सच बात यह है कि सत्ता का केन्द्रियकरण चरित्र पतन में सहायक होता है। भारत की सम्पूर्ण सत्ता संसद के पास सिमट गई है। हर बड़े नेता का चमचा भी कुछ न कुछ लाभ लेने के लिए ही जुडा हुआ है। ऐसी स्थिति में उन्हें इमानदार बनने का प्रवचन देना बेकार की बात है। इसका समाधान तो यह है कि संसद के अधिकार कम कर दिये जाये जिससे राजनेताओं के भ्रष्टाचार के अवसर कम हो जाये। यही सोचकर हम लोगों ने दो सुझाव दिये है कि संसद के संविधान संशोधन के असीम अधिकारों में कुछ कटौती हो तथा सरकारों के परिवार गॉव तक के अधिकार कम होकर नीचे की इकाईयों में बट जावें।

(6)श्री रामचन्द्र राम, अधिवक्ता,डालटनगंज,पलामू,उ0प्र0 16274

प्रश्नः— संविधान को जेल खाना से मुक्त कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं सहमत हूॅ मुझे बराबर ज्ञानतत्व मिलता है अंक 22 वर्ष 2013 से 16 से 30 तक 2015 जून तक प्राप्त है।

आपने ज्ञानतत्व में लिखा है कि चीन हमारा दोस्त,शत्रु,या विरोधी या प्रतिद्वंदी इस पर चर्चा हो। मैं आपकी इस धारणा से सहमत हूॅ कि चर्चा होनी चाहिए साथ ही यह भी चर्चा हो कि साम्यवाद भारत में जन्म लेकर एक दिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था का रुप लेगा?या नही ? भारत में मुस्लिम मदरसा की स्थिति क्या है? जहॉ पर 15 अगस्त 26 जनवरी को भी झण्डोत्तोलन नही होता। मुस्लिमों की मनोभावना देश में क्या कहती है?क्या करती है? मोदी के साथ गुलामी का खतरा,कैसे है विस्तृत वर्णन करें? मैं ज्ञानतत्व का प्रशंसक नही हूॅ। चूॅकि आप की व्यंग्यात्मक भाषा जन मानस की समझ से बाहर है। आप राजनैतिक व्यवस्था कैसी चाहते है?आज तक समझ में नहीं आया? दिल्ली मे ही वैचारिक क्रांति है या भारत के अन्य हिस्सों में भी। चूॅकि आप केजरीवाल का भक्त लगते है। पढने से मालूम होता है। मैं सिर्फ पाठक हूॅ। ज्ञानतत्व क्या कहता है वह मैं पढ़ता हूॅ।

उत्तरः— संविधान को संसद के जेल खाने से मुक्त कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इस दिशा में सक्रिय भी है। जिन चार मुद्दो पर हम जनमत जागरण शुरु कर चुके है उनमें से दूसरा मुद्दा यही है। पहला मुद्दा परिवार ,गॉव,जिलो को संवैधानिक अधिकार देना है। इस संदर्भ में दिल्ली के नोएडा शहर में 2,3,4 अक्टूबर को विधिवत एक संगठन बनना शुरु हो जायेगा। जिसमें देश भर के कई सौ लोग भाग लेंगे। इसके बाद अक्टूबर 2017 तक पूरे देश में विकास खण्ड स्तर तक संगठन बनाने की तैयारी है। अक्टूबर 17 में जंतर मंतर पर दस दिनों का एक धरना देकर इस आन्दोलन की शुरुवात की जायेगी।मैं आपको स्पष्ट कर दूॅ कि हमारी लडाई सरकार से नही है बल्कि संसद से है और वह भी संसद के किसी विधायी या कार्यपालिक अधिकार से नही है,हमारी लडाई सिर्फ संसद के संविधान संशोधन संबंधी असीमित अधिकारों को सीमित करने तक सीमित है। इसका अर्थ है कि हम संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना चाहते है। हम चाहते है कि राज्य हमारा प्रबंधक हो,प्रबंधक अपने को समझे न कि सरकार ।

दुनिया में राजनैतिक स्तर पर चार प्रकार की कार्यप्रणालियॉ है (1) विचार मंथन अर्थात् ब्राह्मण प्रणाली जो प्राचीन समय में भारत में रही है(2) शक्ति प्रयोग अर्थात् क्षत्रिय प्रणाली जो इस्लामिक राष्ट्रों में ज्यादा प्रचलित हैं।(3) वैश्य प्रणाली जो सेवा ,प्रेम,सद्भाव,लोभलालच और धन के सहारे चलती है यह प्रणाली मुख्य रुप से पश्चिम के देशों में है।(4) शूद्र प्रणाली है जो साम्यवाद का मुख्य आधार है। क्षत्रिय प्रणाली और शूद्र प्रणाली में यह फर्क होता है कि क्षत्रिय प्रणाली अंधाधुंध हत्याओं का सहारा नहीं लेती न ही अन्य प्रणालियों को समाप्त करके अपना विस्तार करती है। लेकिन शूद्र प्रणाली जो साम्यवाद का मुख्य आधार है वह असीमित हिंसा का प्रयोग करती है तथा अन्य सभी प्रणालियों को शुन्यवत करके अपना विस्तार करती है। क्षत्रिय प्रणाली अर्थात् इस्लाम में परिवार व्यवस्था को तथा समाज व्यवस्था को नष्ट नही किया जाता। किन्तु साम्यवाद में परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाता है। साम्यवाद एक समाज विरोधी विचार था जो अब धीरे–धीरे पूरी दुनिया द्वारा अस्वीकृत हो रहा है। इसी तरह इस्लामिक प्रणाली भी अतिवाद की तरफ बढने के कारण संकट में आ रही है यही कारण है कि मृत्प्राय साम्यवाद तथा संकट ग्रस्त इस्लाम ने कम से कम भारत में तो एक दूसरे की मद्द करने के लिए हाथ मिला लिया है । मैं निश्चिंत हूॅ कि साम्यवाद न भारत में सफल हो पायेगा न दुनिया में। मुस्लिम मदरसों की स्थिति भी अपना अस्तित्व खो रही है। यदि संघ परिवार शिवसेना सरीखे लोग न चिल्लावें तो अपने आप लोकतांत्रिक तरीके से या तो

मदरसे अपने को बदल लेगें अथवा समाप्त हो जायेंगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकतंत्र मजबूत हो रहा था और समस्याएँ बढ़ रही थी। क्योंकि सोनिया गॉधी और मनमोहन सिंह दो विपरीत ध्रुवो पर खडे होकर कार्य कर रहे थे। नरेन्द्र मोदी के आने के बाद सत्ता का केन्द्रीयकरण हो रहा है और समस्याएँ लगातार सुलझ रही है। भारत की जनता दोनों में से किसे पसंद करेगी यह भविष्य बतायेगा। मैं उस समय मनमोहन सिंह के पक्ष में था और अब मोदी के पक्ष में हूँ। फिर भी यदि मनमोहन सिंह स्वतंत्र रुप से आगे आये तो मैं उसका स्वागत करुँगा।

मेरे विचार में राजनैतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सुरक्षा और न्याय को अपना दायित्व समझे तथा अन्य कार्य परिवार,गॉव,जिला,प्रदेश और केन्द्र को सौंप दे। केन्द्र में एक सरकार हो जो पुलिस सेना,वित्त विदेश,न्याय तक अपने को सीमित करके बाकी सब काम अन्य इकाइयों को सौंप दें जिसमें एक केन्द्रीय इकाई भी हो किन्तु वह सरकार से भिन्न हो। मैं केजरीवाल का न पहले भक्त था न अब हूँ । यह अवश्य है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के पूर्व मुझे विश्वास था कि केजरीवाल भी विकेंद्रित प्रणाली की दिशा में बढ सकते है। यही कारण था कि मैं मनमोहन सिंह के बाद नीतिश कुमार का समर्थक रहा और अब भी हूँ क्योंकि नीतिश कुमार और मनमोहन सिंह सत्ता के प्रयोग में स्पष्ट दिख चुके है। जबकि अरविंद केजरीवरल अब दिख रहे है और जो अन्य सभी राजनेताओं की अपेक्षा अविश्वसनीय चेहरा दिखाकर उभर रहे है। जिस तरह अरविंद जी ने अपने एक मंत्री का गलत पक्ष लेकर क्षमा याचना की वहॉ तक पूरी तरह साफ निर्णय करने की स्थिति नही थी किन्तु उसके बाद के कुछ प्रकरण और अभी अभी अलका लांबा का प्रकरण जिसमें उन्होने पत्थर लगने के पूर्व अथवा बाद में विपक्षीय भाजपायी नेता की दुकान में घुसकर तोडफोड की उसने मेरे मन में और अधिक अविश्वास भर दिया है। देखिये भविष्य में यह अविश्वास कहॉ तक जाता है। फिर भी अभी अरविंद केजरीवाल के विषय में मैं किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुँचा हूँ।

(7)ओमकार मिश्र,बाराबांकी उ0प्र0,ज्ञानतत्व 7909

प्रश्नः— अंक 316 में आपने कश्मीर के पंडितो की बात लिखी है। वहॉ उनके जवान बेटे बेटियों के साथ जो हुआ उससे क्या रोंगटे खडे नही होते है? क्या उन लोगो को अपने स्वजनों तथा अपने पैतृक स्थान से लगाव नही है। इसलिए सरकार को उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर उन्हें वहॉ बसाना ही चाहिए। आप जो बस्तर की बात करते है। तो इसके जिम्मेदार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, के व्यापारी है जो रीवा, कटनी, विलासपुर,बैकुंठपुर,जबलपुर, अम्बिकापुर,रायपुर, रायगढ़,कठघोरा , चिरमिरी, दंतेवाडा में आकर कोयला खदानों के पास अपने व्यापार का विस्तार दिये, और आदिवासियों का आर्थिक मानसिक शारीरिक शोषण करते रहे। दर्जनों आदिवासियों से केवल खाने और कपड़े का लालच देकर बन्धुआ मजदूर की तरह काम लेते है। आपके ज्ञानतत्व से अब तक समझ में नही आता कि आप किस तरह का बदलाव चाहते है। आप के अंक 311 में श्रीमान केजरीवाल का महिमा मंडन बहुत है लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री श्री पारिकर जी मुख्यमंत्री स्कूटर से चलते थे,चीन के राष्ट्रपति साइकल से चलते थे लेकिन श्रीमान केजरीवाल को करोडो की गाडी तथा विलासिता चाहिए। कहॉ चला गया उनके कोरे भाषण और नैतिकता का स्तर?

श्रीमान केजरीवाल चुनाव अपने नैतिक आधार पर नही बल्कि 30—40 प्रतिशत विहार के लोग जो दिल्ली की झुग्गी झोपडी में साधन विहीन थें, उनकी वजह से जीते लेकिन दिल्ली वासियों की पानी, विजली, सफाई, सुरक्षा , शिक्षा स्वास्थ्य की जरुरत नही दिखाई पडती है। आप संविधान की बात करते है। जहॉ पं0 भीमराव जी एक अध्यापक थे, अपने बच्चों पत्नी गाव समाज को छोड कर श्रीमान अम्बेडकर को पाला पढाया और आगे बढाया और पं0भीमराव जी अंतिम सासें गिन रहे थे तो उस समय श्रीमान अम्बेडकर जी इंग्लैण्ड में प्रवास पर थे। आज उन अम्बेडकर जी के अनुयायी पं0 भीमराव जी के वंशजों को शहर गॉव बाजार के चौराहे पर अपमानित कर रहे है। इसका जिम्मेदार कौन है। आप से प्रार्थना है। कि इसका स्पष्ट उत्तर अगले ज्ञानतत्व के अंक में अवश्य देने की कृपा करें।

उत्तरः— आपने बस्तर के विषय में जो लिखा वह आपकी सुनी सुनाई बातो पर आधारित है वास्तविकता नहीं। सच्चाई यह है कि जिस बस्तर में नक्सलवाद तेजी से फैला वहॉ पिछले 40—50 वर्षो से बाहर के लोगो को जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। रीवा, कटनी, विलासपुर,बैकुंठपुर,जबलपुर, अम्बिकापुर,रायपुर, रायगढ़,कठघोरा , चिरमिरी,

दंतेवाडा आदि शहरों का नाम लिया है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि इन सब में से किसी भी क्षेत्र में नक्सलवाद नही आया और न आने की संभावना है। सिर्फ रामानुजगंज में नक्सलवाद आया था और वहॉ से हार थक कर चला गया। सच बात यह है कि आदिवासी गैर आदिवासी की भावना ही खतरनाक है। लेकिन यह भावना समाप्त नही हो पा रही है। केजरीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन के प्रारंभिक लक्षण दिख रहें थे जो मनोहर परिकर ने नही थे, चीन के राष्ट्रपति में तो हैं ही नही। यही कारण है कि सबके अन्दर त्याग होते हुए भी मैने केजरीवाल पर अधिक ध्यान दिया। त्याग भी महत्वपूर्ण होता है, किन्तु व्यवस्था परिर्वतन की कीमत पर नहीं।

आपने भीमराव जी को अम्बेडकर जी का अध्यापक लिखा जबकि मेरी जानकारी अनुसार भीमराव अम्बेडकर के गुरु का नाम अम्बेडकर था और अम्बेडकर जी ने अपने ब्राहमण गुरु के नाम पर अपना नाम अम्बेडकर रखा। आपकी बात सच है कि मेरी यह भविष्य में पता चलेगा। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अच्छे पिता के पुत्र का भी वैसा ही आचरण हो। अम्बेडकर जी के गुरु के परिवार वालों का आचरण कैसा होगा उसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए। न तो यह आवश्यक है कि गुरु भीमराव जी के परिवार वालो का आचरण ठीक ही हो, न ही यह आवश्यक है कि अम्बेडकर जी के अनुयायियों का ।

(8) सत्यपाल शर्मा,बरेली,उ0प्र, ज्ञानतत्व–6894

प्रश्नः– कृपया निम्न विषय पर अपने विचार से अवगत करायें, मोदी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया इसमें शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी आई लेकिन निम्न स्तर पर भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है। महंगाई बढ़ी है, आम आदमी की हालत खस्ता हुई है, आम आदमी के बच्चों के लिए रोजगार नही है, प्रधानमंत्री के ''मेक इन इंडिया'' के सपने में बडी और आधुनिक कंपनियों को लाभ प्रोत्साहन रियायते दी जा रही हैं। जब घर में दाल चावल नही है तो प्रेशर कुकर में निवेश व्यर्थ है। बाजार में मांग के अभाव में निवेश नही हो सकता है। भारत का सही मायने में विकास कुटीर उधोग के विकास से होगा। आम आदमी को ट्रेन में सफर करते समय जगह नही मिलती वहीं बुलेट ट्रेन चलाने की योजना आत्मघाती होगी। मोदी आम जनता की तकलीफों को चालाकी भरी बातों से दूर करना चाहते हैं। ट्रेनों में जनरल बोगी की संख्या में वृद्धि की जाये जिससे आम जनता सुगमता से यात्रा कर सके। जनधन योजना में लाखों व्यक्तियों के खाता संचालित नही हो रहे हैं। बैंको में इतनी भीड रहती हैं कि आम जन की बात नही सुनी जा रही है। अच्छे भाषण देने से जमीनी हकीकत नही बदलती है। सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन देने के लिए नोट छापने से निवेश घटता है।

उत्तरः– ऐसा लगता है कि आपने पत्र लिखने में केवल सुनी सुनाई चचाओं को आधार बनाया। आपने न तो अपने अनुभव का उपयोग किया न ही जानकारी दी। भ्रष्टाचार उच्चस्तर पर घटा है तो निम्नस्तर पर भी घटना शुरु हुआ है। कैश सबसिडी अथवा ऑनलाइन करोबार अथवा निजीकरण निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार घटाने की शुरुवात कर चुका है। मैं नही समझा कि आपको महंगाई कहॉ और कैसे बढ़ी हुई दिख गई। सरकारी आंकडे बिल्कुल झूठे है क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन बढाने के लिए झूठे आंकडे तैयार कर रहे है। मैं जो कह रहा हूँ वह गंभीरता से कह रहा हूँ और मैं किसी स्तर पर इसे सच सिद्ध करने को तैयार हूँ । धान चावल 25 प्रतिशत गेहूँ 10 प्रतिशत कपडा 20 प्रतिशत लोहा 40 प्रतिशत तथा अन्य अनेक वस्तुएँ भी इसी तरह सस्ती हुई है। जमीनों के दाम लगातार घट रहें है होटलों का किराया भी 20 प्रतिशत कम हुआ है फिर भी पता नही,आपको केवल दालों और प्याज को देखकर इतनी भारी चिंता कैसे हो गयी। टी बी में महॅगाई का रटारटाया एपीसोड तथा वास्तविक धरातल में बहुत फर्क होता है। आपने लिखा कि बेरोजगारी बढ़ी है यह भी पूरी तरह असत्य है। 2005 में एक मजदूर को भारत के पिछडे क्षेत्र में एक दिन की मजदूरी के रुप में चार किलो गेहूँ मिलता था और पश्चिमी उ0प्र0 में 7 किलों। आज पिछडे क्षेत्रों में 10 किलो गेहूँ एक दिन की मजदूरी में मिलता है और पश्चिमी उ0प्र0 में करीब 18 किलो। ऐसे कुछ घर खोजकर निकालिये जहॉ दाल चावल खाने के लिए नही है यहॉ तक कि बिल्कुल अपंग या भिखारी भी अब उस स्थिति में नही है कि वे सडको पर पड़ी जूठन उठाकर खाते हो। मैं नही समझता कि पैसेंजर गाडी में चलने में आपको क्यों दिक्कत आ रही है कि आपको एक्सप्रेस गाडी में पैसेंजर के किराये में चलने की सुविधा प्रदान की जाये। यदि मैं रेल मंत्री होता तो ट्रेन किराया दोगुना करके उससे प्राप्त सारा धन उन क्षेत्रों में नयी ट्रेन चलाने में लगा देता जहॉ ऐसी सुविधा नही है। मैं नही समझता कि जनधन योजना शुरु होने के पूर्व आपकी नजर में वर्तमान

की अपेक्षा आर्थिक स्थिति कैसी थी। मैं इस सम्बंध में स्पष्ट हूँ कि नरेन्द्र मोदी ने अच्छाई के सारे अच्छे कीर्तिमान बना लिये है यह कहना गलत है और मैं भी नहीं कहता। किन्तु मैं आश्वस्त हूँ कि वर्तमान समय में पिछली सभी सरकारों की अपेक्षा वर्तमान सरकार कई गुना अच्छा काम कर रही है।

(9)जगशरण उपाध्याय,मेरठ,उ0प्र0, ज्ञानतत्व–9428

प्रश्नः– सामान्य जन जीवन में परिवारों की भूमिका समाज की संरचना में महत्वपूर्ण रही है। परिवारों ने अपना एक छत्र वोट देकर लोकतांत्रिक सरकार बनाने में सहयोग प्रदान किया है। सरकार का भी कर्तव्य होता है कि परिवारों का उन्नयन प्रत्येक स्तर पर आगे बढे। जागरुकता के बल पर समाज की संरचना में सुव्यवस्था पैदा करें। किन्तु परिवार बेदम होने पर उनकी गिरती स्थिति के प्रति उनको सहारा मिलना तो दूर कहीं से आश्वासन भी नही मिलता। ऐसी परिस्थितियॉ आ जाने पर सरकार कौन से दायित्वों का पालन परिवारों के प्रति कर रही है?

उत्तरः– सरकार चाहे किसी अन्य की हो या नरेन्द्र मोदी की। किन्तु कोई भी सरकार अपने अधिकार में कटैती करके परिवारों को देना नही चाहेगी। परिवारों को अधिकार देने के लिए हम आप सबको मिलकर ही जनमत जागरण करना पडेगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि संघ परिवार अन्य मुद्दो पर भले ही भिन्न राय रखता हो परन्तु परिवार सशक्तिकरण पर उसकी सहमति अवश्य मिलेगी। अब तक संघ परिवारों में परिवारों को संवैधानिक अधिकार दिये जाने के मुद्दे पर बिल्कूल चुप्पी साध रखी है। देखते चलिये भविष्य में संघ परिवार को कभी समझ आवे और वह परिवारों को आर्थिक तथा विधायी अधिकार देने में सहमत हो जाये।

(10) श्री मनोज कुमार द्विवेदी प्रवक्ता, ऋषिकेश उत्तराखंड 249201

आपने मेरे प्रश्न का उत्तर 316 (01 से 15जुलाई) में लिखकर मेरा तथा साथ ही मेरे जैसे अन्य पाठक का भी ज्ञान बढ़ाया है इसके लिए आपका धन्यवाद।

आपने पेज न. 3 पर लिखा है कि छ.ग. के बस्तर इलाके में बाहरी लोगों के प्रवेश करने से संबंधित परमिट या कानून का...।

मैं जानना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में बस्तर जिले व कश्मीर की समस्या एक जैसी है? और समाधान भी एक जैसा है क्या?

आपने पेज0 4 पर लिखा है कि मंगल पाण्डे के समान इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो बना सकती है किन्तु स्वतंत्रता की लड़ाई आगे सैकड़ों वर्षों तक टाले जाने का अपराधी भी मान सकती है।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उपरोक्त से संबंधित प्रामाणिक साक्ष्य मिल सकता है? अभी तक मैंने आपके विचार से पूर्व तक इस तरह की टिप्पणी नहीं सुनी है औन ना ही पढ़ा है।

उत्तर– स्वतंत्र भारत मे कश्मीर की समस्या और बस्तर की समस्या की तुलना की जाये तो बस्तर की समस्या कई गुना अधिक गंभीर है। कश्मीर समस्या सन 47 से भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या हे। जिसमे संयुक्त राष्ट्र संघ की भी भूमिका है। यद्यपि भारत का पक्ष मजबूत है किन्तु अब तक न पाकिस्तान माना है न ही संयुक्त राष्ट्र संघ। दूसरी ओर बस्तर मे एक गिरोह द्वारा सशक्त सत्ता परिवर्तन के प्रयास की सफल शुरूआत है। उनकी लडाई बस्तर जिले के भारत से अलग करने की नही है बल्कि उनकी लडाई बंदुक से पुरे देश पर अपना शासन स्थापित करने की है। यही कारण है कि वस्तर की लडाई हमारे लिए उच्च प्राथमिकता है। वस्तर का समाधान करना आसान है और कश्मीर का कठिन। दोनो का समाधान एक नही हो सकता।

मंगल पांडेय ने जो कुछ किया वह एक हिम्मत का काम था। अप्रतिम्म त्याग था किन्तु बिना सोचे समझे भावनात्मक कार्य था। जिसने स्वतंत्रता की योजना पूर्वक तैयार की गई लडाई को भारी नुकसान पहुचाया। यदि यह लडाई अपने ठीक समय से शुरू हुई होती तो संभव है कि परिणाम कुछ दुसरे ही होते । यही सोचकर मैने मंगल पांडेय को अपनी टिप्पणी के साथ जोडा है।

11 शशांक मिश्र भारती, बड़ागांव शाहजहांपुर उ0प्र0– ज्ञानतत्व–10380

प्रश्न– ज्ञान तत्व अंक 316 शाहजहांपुर के पते पर पाकर प्रसन्नता हुई। अपराध और अपराध नियन्त्रण पर आपने सुन्दर व सटीक लिखा है। ललितमोदी प्रकरण और सुषमा स्वराज पर दृष्टिकोण यथार्थ पर आधारित है। देश में राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही अपने–अपने दलों के आधार पर संकुचित हो रहे हैं। कई बार इनके हित देश–समाज का अनेक प्रकार से अहित करने को उत्सुक हो जाते हैं। आम जनता का धन अपव्यय का शिकार होता है। इनके मात्र अतार्किक स्वार्थ सिद्ध होते हैं। इसका उदाहरण है संसद का मानसून सत्र।वह दिन कब आयेगा जब ये सभी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करने के लिए दलीय हित से ऊपर उठ राष्ट्रहित से जोड़ देगे।

इधर याकूब मेमन की फांसी की व्याख्या भी लोगों ने 1993 के सन्दर्भ उसके प्रभावों के अनुसार न कर अपने– अपने चश्में से कर अपनी ही मानसिकता का परिचय दिया है। संभवतः ऐसा भारत जैसे देश में संभव है। ये लोग इस तरह किसका सहयोग कर रहे हैं यह समझा जाना चाहिए और देश की जागरूक जनता को अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करते समय इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए।

उत्तर– आपने याकुब मेनन की फांसी पर हो रही बहस पर टिप्पणी की। मेरे विचार मे ऐसी बहस होना कोई बुरी बात नही है। पक्ष विपक्ष मे विचार मंथन या बहस चलते रहनी चाहिये, किन्तु विचार मंथन या बहस जब क्रिया मे बदल कर सडको पर आ जाती है किसी एक पक्ष के समर्थन या विरोध मे खडी हो जाती है, तब वह चर्चा घातक रूप ले लेती है। वामपंथी और कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मिलकर याकुब मेनन वाले मामले मे एक पक्ष बन गये तो शिवसेना संघ परिवार दुसरा पक्ष। इन दोनो गुटो को पेशेवर तरीके से रोज कुछ न कुछ करना ही है। अतः इनका कोई महत्व मानकर हमे चिंतित नही होना चाहिये।

12 बेचु बी ए, कप्तानगंज कुशीनगर ज्ञानतत्व–4265

प्रश्न– किसी ने कहा है कि नेता झुठ के पेड होते हैं। बात करें विश्व हिन्दू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल जी की। उन्होने अभी हाल ही मे एक बयान देकर देश को चौंका दिया । वे कहते हैं कि 2014 के लोक सभा चुनाव के नतीजों से देश मे एक जनक्रान्ति हुई है। उन्होने दावा किया कि वर्ष 2020 तक भारत हिन्दू राष्ट्र हो जायेगा और 2030 तक पूरा राष्ट्र हिन्दू हो जायेगा । वे जब बयान दे रहे थे तो उस वक्त विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होने यह बात तो कह दी लेकिन वही पलटी मार गये और कहा कि वे साई बाबा के आश्रम गये थे। वहां उनसे साई बाबा ने उक्त बाते बताई। यह वही अशोक सिंघल जी है जो राम जन्म भूमि के बारे मे क्या कहते रहे है और काशी मथुरा के बारे में भी। भारत की जनता को यह सब सुनते सुनते कान पक गये हैं। हर चुनाव मे इस बात की खूब चर्चा आम होती है कि राम लला हम आयेगे। मंदिर वही बनायेगे। पर तारीख नही बतायेगे।

अब देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह के बयानो पर नेताओ से संयम रहने का कहा है इसके बावजूद इस तरह का बयान देश को कहां तक ले जायेगा?

उत्तर– अशोक सिंघल आजम खान क्या कहते है। उसे न प्रधानमंत्री महत्व दे रहे है, न भारत के नागरिक और न ही मैं। जिन लोगो ने तोड फोड करके अपने को स्थापित करने का बीडा उठाया है उन लोगो की अनावश्यक चर्चा करके हम आप अपना समय क्यो नुकसान करे । अनेक नाटको मे यदि विदुषक न हो तो नाटक का एक महत्वपूर्ण अंश कमजोर हो जाता है। किन्तु विदुषक के क्रिया कलाप चर्चा के योग्य नही होते। अशोक सिंघल आजम खांन जैसे विदुषको की चर्चा करके आप अपना महत्व कम कर रहे हैं। अच्छा हो कि अन्य महत्वपूर्ण चर्चा करे।

13 ओम प्रकाश मंजुल, पीलिभित उत्तर प्रदेश ज्ञानतत्व–6011

प्रश्न – धर्म स्थानो पर बंदरो की बढती संख्या खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है। नर के बाद बानर सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसलिय बंदर को पशु नहीं प्राणी कहा गया है। अब बंदरो की भयावहता पर अखबारो मे संपादकीय

लिखने का समय आ चुका है। ताकि बंदरो के विरूद्ध चेतना और जनमत बने तथा सरकार समस्या के समाधान हेतु सोचने पर विवश हो सके। हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूर की सोच रखने मे माहिर है। वे मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया योग इन इंडिया की बाते करते है तो उनके मन मे सांईटिफिक इंडिया की बात भी होगी। उन्हे बकायदा इस समस्या पर एक राष्ट्रव्यापी नीति बनाकर जेनेटिक वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र मे अनुसंधान करने के लिये प्रेरित करना चाहिये ताकि धीरे धीरे अहिंसक ढंग से भारत को वानराधिक्य की समस्या से मुक्त करा कर स्वस्थ एंव निर्भय भारत का निर्माण किया जा सके।

उत्तर– बंदर दो प्रकार के होते है। एक हनुमान के वंषज, दूसरे बाली के वंषज। बाली का भगवान राम ने वध किया था और हनुमान को सुरक्षा दी थी, प्रेम दिया था, सम्मान दिया था। कौन बंदर वाली की संतान है और कौन हनुमान की। यह पहचान देखकर नहीं हो सकती। बल्कि उनकी प्रवृत्ति और उनके किया कलापो से ही हो सकती है। हमारा कर्तब्य है कि हम यह अनुभव करें कि बाली कि संतानों की संख्या बहुत बढ गई है। और उनका वध करने मे कुछ भी गलत नहीं है। सरकार को और समाज को इस विषय मे सक्रिय होना चाहिये।

खबरें इस पखवाडे की

संसद मे गतिरोध–

पिछले एक माह से संसद नही चल पा रही है। विपक्ष का कहना है कि पिछली संसद मे जब भाजपा विपक्ष मे थी तब वह संसद को नही चलने दे रही थी। भाजपा का कहना है कि पिछली बार कांग्रेस सरकार संसद चलानें के जो प्रयत्न कर रही थी, वे सारे प्रयत्न हम कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कि दोनो मे गलत कौन है? विपक्ष हमेशा यह समझता है कि संसद को रोककर वह जनता मे लोकप्रियता प्राप्त करता है और उसी आधार पर वह सत्ता मे आ सकता है। भाजपा भी पहले यही सोचती थी।

मैने पिछले समय मे संसद मे गतिरोध के लिये भाजपा की भरपूर आलोचना की थी। मै अब भी मानता हूँ कि संसद मे अनावश्यक गतिरोध से विपक्ष कि बदनामी अधिक होती है और उसके वोट घटते हैं । कांग्रेस या अन्य विपक्ष इस मामले मे भूलकर रहा है। मेरे विचार से संसद चलने का एक ही उपाय है कि नरेन्द्र मोदी स्वयं संसद मे यह बयान दें कि पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी ने संसद चलाने के मामले मे गल्तिया की थी। अब हम महसूस कर रहे हैं कि वैसा करना गलत था और हम भविष्य मे ऐसा नहीं करेंगे। साथ ही उन्हे यह भी कहना चाहिये कि हमने अपनी मंशा साफ कर दी है। विपक्ष को भी इस विषय मे अपनी धारणा स्पष्ट करनी चाहिये। मेरे विचार में संसद ठीक ढंग से चले इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नही है।

2 झारखंड मे डायन के संदेह मे पांच महिलाओं की हत्या

झारखंड के रांची जिले मे डायन होने के संदेह मे पांच महिलाओं की हत्या कर दी गई। हत्या एक अपराध है और उस आधार पर ऐसा करने वालो को कानून दंडित करेगा। किन्तु आज के विकसित भारत मे समाज में इतना पिछडापन हमारे लिये दुख का विषय भी है और शर्म का भी। यदि भूत प्रेत के नाम पर किसी एक की भी हत्या होती है तो वह एक असाधारण घटना माना जाना चाहिये। यहां तो झारखंड मे पांच पांच महिलाओं की एक साथ हत्या हो जाती है।

मै समझता हूँ कि भारत मे भूत प्रेत या डायन का प्रभाव घट रहा है। दूसरी ओर भारत मे हर मामले मे ग्लोबल वार्मिग अर्थात मानव स्वभाव ताप वृद्धि का प्रभाव बढ रहा है। जो घटना घटी है, वैसी घटनाएं अन्य अनेक साधारण मुददों पर भी हो रही हैं। कहीं गाडी आगे निकालने के विवाद मे होती है तो कही पार्किग के विवाद मे और कही धार्मिक मूददो को उठाकर। हम हिंसा की तरफ बढ रहे हैं। झारखंड मे डायन के नाम पर हुई हत्या का समाधान भूत प्रेंत ओझा डायन का प्रभाव घटाने से तो होगा ही किन्तु वास्तविक समाधान यह है कि समाज मे हिंसा के प्रति बढते विश्वास को रोकने का प्रयास किया जाय। सच बात यह है कि सरकार अपराधियों को दण्ड देने मे या तो बहुत विलम्ब कर रही है या दण्ड मिल नही रहा है, और इस आधार पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति मे स्वयं कानून हाथ मे लेकर तत्काल दंड देने के प्रति विश्वास बढ रहा हे। इन पॉच हत्याओ को उदाहरण मानकर हमे सामाजिक हिसा के विरूद्ध वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिये।

3 आतंकवाद की ताजा घटनाये।

पिछले कुछ दिनों से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों मे आतंकवाद की घटनाएं बढ रही हैं। प्रतिदिन ही कहीं न कहीं मुठभेड हो रही है, और उसमे आतंकवादी तो मर ही रहे हैं, साथ ही भारत के जवान भी मर रहे हैं। यह सच है कि आतंकवादी मुस्लिम कटटरवादी हैं। यह भी सच है कि वे या तो पाकिस्तान के होते है या पाकिस्तान से होकर आते हैं। हमे महसूस करना होगा कि पाकिस्तान मे सरकार आतंकवादी संगठनो के दबाव मे है। यह भी संभव है कि वह उनको रोकने मे सफल न हो या वहां की सरकार मजबूरी मे आतंकवादियों का समर्थन कर रही हो। भारत के सामने विकट स्थिति है कि वह आतंकवाद के संकट के लिये पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार करे? भारत के उग्रवादी हिन्दू समूह चाहते है कि भारत पाकिस्तान के साथ कटटरता से पेश आवे, भले ही युद्ध क्यो न हो जाये। दूसरी ओर दुनिया भर के मुस्लिम आतंकवादी भी यही चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार निपटारा हो ही जाये, भले ही युद्ध क्यो न हो। मै इस विषय मे स्पष्ट हूँ कि भारत को किसी भी तरह युद्ध से बचने का प्रयास करना चाहिये क्योकि युद्ध पाकिस्तान तक सीमित नही रहेगा। आवश्यक नही है कि विजय निश्चित हो। किसी युद्ध से पाकिस्तान को जीत लेना भी कठिन है और जीतने के बाद शान्ति पूर्वक अपने साथ रखना भी। भारत को एक छोटे से भाग कश्मीर पर नियंत्रण बनाने में तो इतनी दिक्कत आ रही है तो पूरे पाकिस्तान को जीतने के बाद क्या होगा यह निश्चित करना कठिन है। औसत मुसलमान न स्वयं शांति से रहना जानता है न ही दूसरों को रहने देना। वह मरना भी जानता है और मारना भी। जबकि औसत हिन्दू इसके ठीक विपरीत होता है। ऐसी परिस्थिति मे यदि भारत पाकिस्तान को किनारे करके आतंकवाद के विरूद्ध वातावरण बनाये तो भारत के लिये विश्व स्तर पर बहुत समर्थन मिलेगा। यह बात जानते हुए कि आतंकवादी पाकिस्तान से होकर आते रहे हैं। फिर भी हमें तब तक शान्त और धैर्य रखना चाहिये जब तक पाकिस्तान की सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका न हो अथवा पाकिस्तान भी भारत के साथ इस आतंकवादी टकराव मे न जुड जावे। भारत के उग्रवादी हिन्दू तथा मीडिया भारत सरकार को युद्ध के लिये प्रेरित करने की कोई कसर नही छोडते। परन्तु भारत को सोच समझकर कदम उठाना चाहिये। मुझे तो आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान के उग्रवादी और भारत के उग्रवादी दो अलग अलग विपरीत ध्रुवो पर खडे हैं। दोनों के बीच आसमान जमीन की दूरी है। किन्तु किसी भी मामले में चाहे वह भारत का हो या पाकिस्तान का । दोनो का उददेश्य एक होता है। दोनो की भाषा एक होती है। और दोनो का आंदोलन भी एक सरीखा होता है। यह बडे दुख की बात है कि दोनो उग्रवादी एक ही प्रकार की मिलीजुली भाषा बोलते हैं। युद्ध बिल्कुल अंतिम मजबूरी होता है । युद्ध उन्माद हमेशा घातक होता है । जहां तक उग्रवाद से निपटने का सवाल है तो भारत वर्तमान समय में जिस तरह चल रहा हो उसे उसी तरह चलना चाहिये।

4 किसी खतरे का संकेत तो नही?

भारत मे पिछले दो तीन महिनों से लगातार उपभोक्ता वस्तुओ के मूल्य कम हो रहे है। शक्कर मे पैतीस प्रतिशत तक मूल्य कम हो गये हैं। लोहा तीस प्रतिशत, कपडा पंद्रह प्रतिशत, चावल बीस प्रतिशत, गेंहु दस प्रतिशत तक सस्ते हुए हैं। जमीनो या बने हुए मकानो के दाम भी लगातार कम होने शुरू हो गये हैं। लौज का किराया भी बीस प्रतिशत तक घटा है। सोना चांदी, तांबा तो घटा ही है । सीमेन्ट, लकडी के मूल्य भी रूके हुए है। किन्तु जिस तरह बिक्री कम है उस तरह उनके भी मूल्यो मे गिरावट निश्चित है।

मूल्यो मे गिरावट एक अच्छी बात है । इससे उपभोक्ताओ को राहत मिलती है किन्तु उपभोक्ता वस्तुओ का मूल्य कम होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियो के वेतन नही घटेंगे । मूल्य वृद्धि के सरकारी आंकडे अब भी यथार्थ से कोसो दूर रहकर वृद्धि बताते रहेंगे। इसका परिणाम होगा कि उत्पादक परेशान होंगे। उन्हे अपने उत्पादन का उचित मूल्य नही मिलेगा और संभव है कि उत्पादन मे कमी आ जाये। यदि उत्पादन मूल्य उपभोक्ता मूल्य तथा सरकारी कर्मचारियों के वेतन तदनुसार एकरूपता बनते हुए कमी आती तो बहुत अच्छी बात थी। टी वी और अखबार वाले तो अब भी मूल्य वृद्धि का प्रचार ही कर रहे है। पता नही उनकी दृष्टि गडबड है अथवा वे अपने वेतन घटने की चिन्ता से दुबले होकर यह कर रहे है। मै तो धन्यवाद दूँगा अपने रिजर्व बैक के गवर्नर रघु रमण को जिन्होने चार महिने पहले हो यह भविष्य वाणी कर दी थी कि पूरी दुनिया मे बडी आर्थिक मंदी आने वाली है। इतनी बडी जितनी हमने कल्पना भी नही की होगी। उस समय मुझे भी नहीं लगता था कि वास्तव मे ऐसा कुछ हो सकता है किन्तु अब मुझे ऐसा कुछ कुछ दिखने लगा है कि कही उनकी बात सच न हो जाय।

इतना अवश्य है कि रिर्जव बैक के गवर्नर श्री रमण ने एक तरफ तो आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी की दुसरी तरफ आर्थिक मंदी न होने की बात कहकर ब्याज दरे घटाने से इनकार कर दिया । समझ मे नही आया कि उनकी कौन सी बात समझी जाय । फिर भी चाहे रमण जी भले ही कुछ भी कह रहे हो किन्तु यथार्थ यह है कि भारत मे लगातार आर्थिक मंदी का वातरवरण है।

प्रिय बंधु,

आप हमारे व्यवस्था परिवर्तन अभियान से निरन्तर सम्पर्क में हैं। अभियान को किसी परिणाम तक पहुॅचाने के लिए एक संगठन की रुपरेखा बनी है. जिसका कार्यालय दिल्ली में खुला है। संगठन तीन प्रकार की इकाईयों में विभाजित करके बन रहा है (1) पूरे भारत में सौ लोकप्रदेश (2)एक लोक प्रदेश में सौ लोक जिले (3) एक लोक जिले में एक सौ गॉव।(1) इस प्रकार एक लोक प्रदेश में लगभग सवा करोड़ की आबादी होगी। (2)एक लोक जिले में लगभग सवा लाख की आबादी होगी तथा (3) एक गॉव की लगभग सवा हजार की आबादी होनी चाहिए। शहरों को भी इसी आबादी के अनुपात में बॉटा जाएगा। पूरे भारत के लिए लगभग सौ लोगों की केन्द्रीय कार्य समिति, एक लोक प्रदेश के लिए सौ लोगों की कार्यकारिणी तथा गॉव के लिए दस लोगों की कमेटी बननी है। इन कमेटियों का गठन आपके द्वारा अथवा आपकी सहायता से होना है। लोक प्रदेश, लोक जिला और गॉव की सीमाओं का निर्धारण दो, तीन, चार अक्टूबर को होने वाली केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में करेंगे।

हम–आप मिलकर ही इस योजना को पूरा कर पाएगे। दो और तीन अक्टूबर को दिल्ली तथा दिल्ली के आस–पास के जिलों को छोड़कर शेष भारत पर चर्चा केन्द्रित रहेगी तथा चार अक्टूबर को दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) पर चर्चा केन्द्रित होगी। आप भी दिल्ली की इस बैठक में सम्मिलित होंगे तो कार्यक्रम के नीति निर्धारण तथा भविष्य की योजना बनाने में हमको सुविधा होगी। आपके निवास तथा भोजन की व्यवस्था कार्यालय करेगा। आवागमन व्यय आप स्वयं वहन करेंगे अथवा उसके लिए आप चन्दा भी ले सकते हैं।

आपसे निवेदन है कि आप जिम्मेदार साथियों को बैठक मे आने की कृपा करेंगे।

केन्द्रीय कार्यालय– बनारस चौक अम्बिकापुर सरगुजा (छत्तीसगढ) 497001	शिविर कार्यालय राजपूत निवास, ए–20, फस्ट फलोर, लेफ्ट साइड, दूसरा 60 फुटा रोड, मोलडबन्द एक्सटेंशन, बदरपुर, दिल्ली–110044 vyavasthapak@rediffmail.com बैठक स्थल–सेक्टर–55, बारात घर प्लाजा होटल के पास, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर	बजरंगमुनि 09617079344